और कारीगरों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरित राशि और मार्च 1990 तथा मार्च 1991 (अद्यतन उपलब्ध) के अन्त तक उक्त श्रेणियों के अग्रिमों की बकाया राशि नीचे दी गई है:—

(खाते लाखों में) (राशि करोड़ रु०)

	कमजोर वर्ग		कारीगर, ग्राम और कुटीर उद्योग	
	खाते	राशि	खाते	राशि
वर्ष 1989–90 (जुलाई–जून) के दौरान संवितरण	57.72	2495.87	2.86	1.49
1990–91 (जुलाई–जून)	53.43	2546.75	3.02	1.89
मार्च 1990 के अन्त तक बकाया	259.01	10110.38	15.34	7.12
मार्च 1991	253.42	10588.69	14.98	7.43

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि कमजोर वर्गों और कारीगरों ग्राम और कुटीर उद्योगों को संवितरित ऋणों और उनके नाम बकाया राशि में वृद्धि हुई है। लेकिन खातों की संख्या में मामूली सी गिरावट आई है। कमजोर वर्गों को ऋण देने के मामले में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्यनिष्पादन की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवधिक आधार पर सुविधा दी जाती है और यदि किसी कमी का पता चलता है तो उसके लिये उपयुक्त उपाय किये जाते हैं। हाल ही में सरकार ने सभी बैंकों से कहा है कि वे कमजोर वर्गों सहित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के लिये निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक कदम उठायें ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों का उत्तर प्रदेश में शाखा विस्तार कार्यक्रम

901. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ग्रामीण बैंकों की शाखायें खोलने हेतु जारी की गई अनुज्ञप्तियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय औसत निवेश की तुलना में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि का निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखायें खोलने के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते। तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के साथ-साथ समाप्त 1985–90 की शाखा लाइसेंसिंग नीति के दौरान उत्तर प्रदेश में शाखायें खोलने के लिये वाणिज्यिक बैंकों को 1110 लाइसेंस जारी किये गये थे। इसके अलावा इसी अवधि

में उत्तर प्रदेश में बैंक शाखायें खोलने के लिये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 302 लाइसेंस जारी किये गये थे ।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उत्तर प्रदेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश की गयी प्रति व्यक्ति राशि 249 रुपये के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले में 207 रुपये थी ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से प्राप्त ऋण

902. **श्री शंकर दयाल सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वर्ष 1993–94 के लिये भारत को ऋण के रूप में कितनी धनराशि स्वीकृत की है ;

(ख) उक्त ऋण सहित भारत पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रदत्त ऋण की कुल कितनी धनराशि बकाया है ; और

(ग) ये ऋण किन निबन्धनों और शर्तों के आधार पर उपलब्ध किये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबार अहमद) : (क) 31 अक्तूबर, 1991 को वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर बोर्ड द्वारा 16560 लाख विशेष आहरण अधिकार (एस०डी०आर०) की राशि स्वीकृत की गई थी । 18 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार हमने 14250 लाख विशेष आहरण अधिकार (एस०डी०आर०) पहले ही आहरित कर लिये हैं ? 2310 लाख एस०डी०आर० की राशि अभी शेष है, जिसे मई, 1993 में आहरित करने की योजना है,।

(ख) 2 मार्च, 1993 तक की स्थिति के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कुल बकाया ऋण 34330055 लाख एस०डी०आर० हैं ।

(ग) इस ऋण की वापसी अहरणों आहरण की तारीख से 3 वर्ष 3 तीन बाद से शुरू करके आठ बराबर तिमाही किश्तों में परिवर्तनीय ब्याज दर पर दी जाती है जिसे कतिपय समायोजनों सहित प्रचलित एस०डी०आर० ब्याज दर के आधार पर समय-समय पर निर्धारित किया जाता है, और इस पांचवें वर्ष में पूरा कर दिया जाता है । आजकल ब्याज दर 6.58 प्रतिशत है ।

India's Export Earning

903. SHRI B. K. HARIPRASAD: Will the Minister of FINANCE be pleased to state;

(a) whether it is a fact that country's export growth is not catching up as targeted; and

(b) if so, whether this will adversely affect the Balance of Paymen position with the imminent danger of debt trap?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Against the target of US dollar 20 billion for 1992-93, exports during April-December 1992 were of the order of US dollar 16.6 billion. Exports during the full year 1992-93 are not likely to exceed US dollar 19 billion.

(b) The balance of payments' current account deficit for 1992-93 estimated to be around US dollar 7 billion reflects the revival of imports to more normal levels. This deficit is being financed through a combination of traditional financing sources and exceptional financing.